Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 9, June-2019, ISSN 2230-7540

झारखंड में शिक्षा की महत्ता एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की रूपरेखाएं

Mukesh Kumar*

Research Scholar, Department of Political Science, Ranchi University, Ranchi

सार – ***शिक्षा की महत्ता को देखते हुए भारत के संविधान की धारा-246 के तहत् शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। स्कूली शिक्षा 4 (चार) चरणों यथा प्राथमिक (कक्षा-1 से कक्षा-5), उच्च प्राथमिक (कक्षा-6 से कक्षा-8), माध्यमिक (कक्षा-9 से कक्षा-10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा-11 एवं कक्षा-12) का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इस नीति का कार्यक्रम 1992 एवं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सभी बच्चों को गुणवत्त शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित कराना है। शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु झारखंड राज्य सरकार विभिन्न केन्द्रीय योजनायें यथा - सर्व शिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा योजना एवं राज्य योजनाओं-यथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, निःशुल्क पोशाक एवं स्कूल किट वितरण, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, निःशुल्क साईकिल वितरण, इंटरमीडियेट स्तर तक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा, सरकारी विद्यालयों के कक्षा-9 से कक्षा-12 तक की सभी छात्राओं को निःशुल्क पोशाक, पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी योजना के माध्यम से सतत् प्रयत्नशील है।***

----------X----------

परिचय

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण ही मुख्य चुनौती है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर से $2 स्तर तक की शिक्षा में गुणवत्ता लाना प्रमुख ध्येय है। राज्य सरकार ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल के तीन वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये स्कूल में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण करते हुए पचासी प्रतिशत (85%) स्कूलों में बेंच-डेस्क तथा विद्युत व्यवस्था लगभग रुपया आठ सौ (800) करोड़ के व्यय पर सुनिश्चित की है। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक शत्-प्रतिशत स्कूल में यह सुविधा सुनिश्चित की जायेगी।

साक्षर भारत

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की रूपरेखाएं पिछले 20 या कुछ वर्षों में बदलावों से गुजरी हैं। ज्यादातर जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया। अब भारत सरकार ने साक्षर भारत योजना की शुरूआत की है। इस योजना का उद्देश्य महिला और पुरुष साक्षरता दर के बीच अंतर को कम करके साक्षरता स्तर को बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना है। साक्षर भारत अभियान के तहत, साक्षरता दर में सुधार के लिए जोर दिया गया है। वर्तमान में, साक्षर भारत स्कीम का विस्तार भारत सरकार के विचाराधीन है। सरकार तीन वर्षों के अंदर छह जिलों में महिला साक्षरता दर को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है। एसडीजी कार्य योजना के अनुरूप इस कार्यक्रम को भी चलाया जायेगा। अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंध करते हुए निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इस योजना से 16 लाख स्त्री-पुरुष लाभान्वित होंगे। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 2500.20 लाख केन्द्रांश एवं 1680.00 लाख राज्यांश का व्यय प्रावधानित करने का प्रस्ताव है।

1. वर्तमान सरकार ने अपनी कार्य अवधि में 18,431 शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित कराया है। प्रारम्भिक विद्यालय की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों पर उम्र सीमा में छूट देकर स्थायी रोजगार का अवसर दिया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई झारखण्ड कर्मचारी चयन

www.ignited.in

आयोग द्वारा की जा रही है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 तक में पूरी होने की संभावना है।

2. शिक्षकों के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं यथा हो, संथाली, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुख, बंगाली एवं उड़िया में भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

3. अंग्रेजी भाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिये विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों यथा: ब्रिटिश कॉउन्सिल, अरविन्दो सोसाईटी, सम्पर्क फाउन्डेशन आदि से एम.ओ.यू. कर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

4. कक्षा-8 में गणित एवं विज्ञान में राज्य के छात्र राष्ट्रीय औसत से अच्छी स्थिति में हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) एवं असर (ए.एस.ई.आर.) द्वारा बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक है। वर्तमान चक्र का परिणाम प्राप्त हो गया है तथा झारखण्ड राज्य के क्रम में परिणाम उत्साहवर्द्धक है, जिसकी समीक्षा की जा रही है।

5. राज्य में आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा में सुधार हेतु नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर सभी प्रमण्डलों में इंटर तक समतुल्य व्यवस्था हेतु दुमका, चाईबासा, रांची में विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। हजारीबाग के विद्यालय को इंटर स्तर तक उत्क्रमित किया गया। इस तरह पूर्व की बारह सौ (1200) की क्षमता को पैंतीस सौ (3500) छात्र संख्या तक पहुँचाया गया।

6. सभी प्रखण्डों में कस्तुरबा तथा झारखण्ड आवासीय विद्यालय स्थापित कर इसकी क्षमता साठ हजार (60000) से बढ़ाकर नब्बे हजार (90000) की गयी है। कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रायें व्यावसायिक कोर्स, नर्सिग, पोलिटेकनिक, बैंड बाजे, कला एवं संस्कृति आदि में अपना विशिष्ट स्थान बना रही हैं।

7. सुरुचिपूर्ण शिक्षा के विकास हेतु शिक्षक समागम, बाल समागम, स्कूली खेल-कूद, बाल संसद इत्यादि को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा कराये गये बाह्य मूल्यांकन एन.ए.एस. सर्वे में राज्य की प्रगति उत्साहवर्द्धक रही है। राज्य के एक हजार (1000) पंचायतें शून्य ड्रॉप आउट तथा पांच सौ (500) पंचायतें शिक्षित घोषित हो चुकी हैं।

8. प्रथम बार मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना कार्यक्रम के तहत् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में क्रमशः 911, 961 एवं 929 छात्र-छात्राओं को क्रमशः दिल्ली एवं आगरा, कोलकाता एवं भुवनेश्वर तथा बेंगलूर एवं मैसूर की यात्रा करायी गयी। इससे सुदूर गांव के छात्रों को देश में हो रही अच्छे कार्यों की जानकारी मिलेगी।

9. प्रथम बार पुस्तकालय आन्दोलन को आज के इलेक्ट्रानिक युग में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 225 पुस्तकालयों का संचालन प्रारम्भ किया गया। यह प्रक्रिया सतत् रूप से जारी है। ई- लाईब्रेरी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिया जायेगा।

10. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आई.टी. का प्रयोग कर स्मार्ट क्लास रूम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कोर्स कन्टेन्ट उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

11. ज्ञानोदय योजना के तहत् गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने तथा ऑन लाईन सूचना प्रेषण एवं रियल टाईम मॉनीटरिंग के लिये प्रत्येक विद्यालय को कम्प्यूटर डिवाइस टैब से युक्त करने हेतु 41 हजार टैब जैप आई.टी. द्वारा क्रय कर उपलब्ध कराया गया है। इसका उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा। इससे शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति का प्रतिदिन मॉनेटरिंग तथा अन्य प्रतिवेदन प्रेषण किया जा सकता है।

12. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 160 माध्यमिक विद्यालयों एवं $2 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का पठन-पाठन प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रत्येक विद्यालय में दो-दो ट्रेड रखे गये हैं। प्रत्येक ट्रेड में नामांकन क्षमता 35 रखी गयी है। इस योजना के तहत् राज्य में 17891 छात्र-छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसका विस्तार

www.ignited.in

मानक का पालन करने वाले विद्यालयों में वर्ष 2017-18 में किया जायेगा।

13. विभागीय अधिसूचना संख्या 681 दिनांक 26.04.2017 द्वारा आकांक्षा कार्यक्रम योजना को कक्षा-9 एवं कक्षा-11 हेतु भी लागू कर दिया गया है। इस प्रकार इस योजना के तहत् सरकारी विद्यालयों के कक्षा-9 से कक्षा-12 तक नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र-छात्रायें लाभान्वित हो रहे हैं।

14. राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम में 41 मेडिकल तथा 46 इंजीनियरिंग की कोचिंग हेतु छात्र-छात्रायें नामांकित हैं तथा जिलास्तरीय कोचिंग में 740 छात्र-छात्रायें मेडिकल कोचिंग तथा 869 छात्र-छात्रायें इंजीनियरिंग कोचिंग में नामांकित हैं। इसका सुदृढिकरण किया जाना है। राज्य में दिनांक 01.04.2015 तक मात्र 434, $2 विद्यालय संचालित थे। $2 विद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र में 99 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए अद्यतन विद्यालयों की संख्या 864 हो गयी है । परन्तु इन विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। इन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला सुविधा तथा स्मार्ट क्लास की सुविधा गुणवत्त शिक्षा हेतु आवश्यक है। अगर पुराने कार्यक्रमों पर आश्रित रहा जाता है तो इसमें समय लगेगा। अतः इस नयी योजना के रूप में मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्नयन योजना आगामी वित्तीय वर्ष से लागू जा रही है।

15. राज्य सरकार के प्रयास से विगत वर्षों में प्राप्त की गयी तुलनात्मक उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नवत् देना चाहेगे।

उपसंहार

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को विकसित किया जायेगा।पर अनुश्रवण करने के साथ-साथ एस.एम.एस. अनुश्रवण की भी व्यवस्था है तथा ई. विद्यावाहिनी सॉफ्टवेयर से भी इसे जोड़ने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सभी विद्यालयों में एल. पी.जी. गैस की व्यवस्था की जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत् चावल की आपूर्ति प्रत्येक विद्यालय में ससमय स्कूल डोर तक करने हेतु "डोर-टू-डोर व्यवस्था लागू की गयी है। तथा हथालन व्यय में राज्य सरकार ने अतिरिक्त राज्यांश देने का निर्णय लिया है। राज्य के लगभग 83 हजार रसोईयों का प्रशिक्षण भी चरणबद्ध तरीके से विशिष्टतापूर्वक कराया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों, जिसमें भूमि एवं पर्याप्त जल उपलब्ध है, उन विद्यालयों में आगामी वर्ष से किचेन गार्डेन लागू किया जाना प्रस्तावित है, ताकि छात्र-छात्राओं को अपने ही विद्यालय परिसर से साग-सब्जी आदि की आपूर्ति हो सके। बालिकाओं के लिये निःशुल्क साईकिल योजना, बालिकाओं हेतु इंटरमीडियेट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सहायता योजना, बालिकाओं को निःशुल्क पोशाक, पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से एक ही अंब्रेला योजना मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत संचालित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ज्ञानोदय योजना में ही शिक्षक योजना, सेमिनार एवं सिम्पोसियम योजना को भी शामिल किया गया है।

सन्दर्भ

1. कार्टर, वी. गुड (1973). "डिक्शनरी ऑफ़ एजूकेशन थर्ड एडी". मैग्राहिल बुक कम्पनी.

2. मेयर, आर. (2008). "द रिर्सच प्रोसेस इन एज्यूकेशन". न्यूयार्क, आई.एन.सी.

3. महन्ते, जगन्नाथ (2008). "स्टडीज इन स्कूल एज्यूकेशन". नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन.

4. माथुर, बी. एस. (1985). "स्टडीज इन इण्डियन एज्यूकेशन". नई दिल्ली, आर्य बुक डीपो.

5. मलिक, पवन एवं बलूनी, अनूप (2014). शिक्षा: र्दानिक एवं सामाजिक आधार". फरीदाबाद, बाला जी पब्लिकेशन.

6. पुरोहित, एच.सी. एवं अजय (2009). "रिसर्च मैथोडोलॉजी टूल्स एण्ड टेक्निक्स". नई दिल्ली, श्री पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स.

7. पाठक, चन्द्र भूषण (2012). "शिक्षा का अधिकार". इलाहाबाद, अनुभव पब्लिसिंग हाउस.

8. पाण्डेय, के.पी. (2008)."शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान". आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन.

9. श्रीवास्तव, डी.एन. (2005). "अनुसंधान विधियाँ". आगरा, साहित्य प्रकाशन.

www.ignited.in

10. "सेवेन्थ ऑल इण्डिया सर्वे". (7संस्करण 2005). नई दिल्ली, एनसीईआरटी.

11. सिन्हा, अमरजीत. (1988). प्राइमरी स्कूलिंग इन इण्डिया. नई दिल्ली, विकास पब्लिकेशन.

12. शर्मा, आर.ए. (2006). "बेसिक एक्सपेरीमेंटल डिजाइन". मेरठ, सूर्या पब्लिकेशन.

13. शर्मा, आर.ए. (2008). "एज्यूकेशनल रिसर्च, डिजाइन ऑफ़ रिसर्च एण्ड रिपोर्ट राइटिंग". मेरठ, आर लाल बुक डिपो.

14. सिंह, सुनील कुमार. (2014), "सामान्य ज्ञान". पटना, लूसेन्ट पब्लिकेशन.

Corresponding Author

Mukesh Kumar*

Research Scholar, Department of Political Science, Ranchi University, Ranchi

mukesh.dtg@gmail.com